क्रम संख्या	खण्ड	स्थिति
4.	मैलानी—कौडियाला	रेल पथ को ऊंचा करने और रीग्रेडिंग का काम पूरा हो गया है। निधि उपलब्ध होने पर इसके क्रियान्वयन पर विचार किया जाएगा।

भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ियों के टिकटों, रेल डिब्बों तथा इंजनों पर प्रयोग की जाने वाली भाषा

†2110. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेल गाड़ियों के टिकटों, रेल डिब्बों तथा इंजनों पर विवरण लिखने के लिये किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया जाएगा; और

(ख) क्या दोनों देशो के रेल टिकटो में समानता अथवा एकरूपता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) टिकटो मे प्रयोग होने वाली भाषाये अंग्रेजी, हिन्दी और उर्दू हैं और उपयोग होने वाली लिपिया रोमन, देवनागरी और अरबी हैं। गंतव्य स्टेशन के बोर्डों पर गतव्य स्थान जैसे लाहौर तथा अमृतसर अंग्रेजी, उर्दू और हिन्दी मे लिखे जाते हैं। केवल अटारी तक चलने वाले भारतीय रेलवे के रेल इंजनो पर उनके नम्बर तथा मालिक रेलवे का नाम एक ओर हिन्दी मे दूसरी ओर अंग्रेजी मे लिखा गया है।

(ख) जी नही।

भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली गाड़ियों में वातानुकूलित डिब्बे और शयनयान

2111. **श्री भागीरथ भंवर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत और पाकिस्तान के बीच प्रति दिन कुल कितनी गाड़ियां चलाने का विचार है और क्या इन गाड़ियों मे प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे भी लगाये जायेंगे। यदि हा, तो उनकी संख्या कितनी होगी ; और

(ख) क्या इन गाड़ियों मे भोजन-यान और शयनयान भी लगाये जाते हैं अथवा लगाये जायेंगे ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) और (ख). 22-7-76 से अमृतसर और लाहौर के बीच एक जोडी दैनिक एक्स-प्रेस गाड़ी चलायी गयी है जिनमे स्थानो की व्यवस्था दो दर्जो मे की गई है अर्थात् "अपर" और "लोअर" जो भारतीय रेलों के वर्तमान पहला दर्जा और दूसरा दर्जा के बराबर हैं। इस गाड़ी मे इस समय वातानुकूलित सवारी डिब्बे, भोजनयान या शयनयान लगाने का कोई प्रस्ताव नही है।

Procurement of Tubulars for Oil Drilling

2112 SHRI ARJUN SETHI Will the Minister of PETROLEUM be pleased to state

(a) whether due to the world-wide stepping up of oil drilling operations tubulars are being purchased and stored the world-over on a large scale,

(b) whether steps have been taken by Government to procure enough